IAS GS World PCS
Committed To Excellence
विशिष्ट संपादकीय सारांश
08 फरवरी 2024
बिजनेस स्टैंडर्ड
पेपर- III (अर्थव्यवस्था)

विनिवेश– केवल कॉस्मेटिक बदलाव नहीं

हाल ही में जारी अंतरिम बजट 2024 में एक वर्गीकरण परिवर्तन किया गया – बजट दस्तावेजों में विनिवेश को प्राप्ति मद के रूप में शामिल नहीं किया गया। इससे पहले, विनिवेश शविविध पूंजी प्राप्तियोंश के तहत एक अलग प्रविष्टि होगी।

विनिवेश के पीछे क्या विचार था?

विनिवेश के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों में सुधार करके उनके प्रबंधन को थोड़ा चुस्त और बाजार की ताकतों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना।

उस सरकार के लिए राजस्व बढ़ाएँ जिसकी वित्तीय स्थिति ख राब थी। सरकारों ने समय-समय पर विनिवेश का उपयोग उद्यमों के सरकारी स्वामित्व को खत्म करने के बजाय घाटे को कम करने के लिए एक साधन के रूप में किया है, इस आर्थिक सिद्धांत को कायम रखते हुए कि सरकार को व्यवसाय चलाने के व्यवसाय में नहीं होना चाहिए।

विनिवेश से जुड़े मुद्दे क्या हैं?

विनिवेश की गति धीमी हो गई है और पिछले दो दशकों में केवल 1 सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण किया गया है। पिछले 32 सालों में सरकार सिर्फ 8 साल में ही विनिवेश लक्ष्य हासिल कर पाई है।

विनिवेश के लिए कौन सा नया दृष्टिकोण इसके प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करेगा?

यहां दो दृष्टिकोण हैं जिन्हें सरकार अपना सकती है।

1) **समय-सीमा-आधारित लक्ष्य:** रणनीतिक पीएसयू के अलावा, अन्य सभी पीएसयू को बाजार के अवसर और शामिल संस्थ. ाओं की उपयुक्तता के आधार पर विनि. वेश या निजीकरण के लिए 5 साल की समय-सारणी के तहत रखा जाना चाहिए।

2) **नए मंत्रालय का निर्माण:** जिन सार्वजनिक उपक्रमों से सरकार बाहर निकलने की योजना बना रही है, उन्हें एक नए विनिवेश मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाना चाहिए (और इसे वित्त मंत्रालय से अलग किया जाना चाहिए)। यह विनिवेश को सरकार के राजस्व जुटाने के दायित्वों से अलग कर देगा।

भारत में विनिवेश का विकास

- भारत में विनिवेश की शुरुआत 1991-92 में हुई जब 31 चयनित सार्वजनिक उपक्रमों का विनिवेश रु. 3,038 करोड़. प्राप्त हुआ था।
- 'विनिवेश' शब्द का प्रयोग पहली बार अंतरिम बजट 1991 में किया गया था।
- बाद में, 1993 में रंगराजन समिति ने पर्याप्त विनिवेश की आवश्यकता पर जोर दिया।
- विनिवेश पर नीति ने गति पकड़ी, जब 1999 में एक नया विनिवेश विभाग बनाया गया, जो 2001 में एक पूर्ण मंत्रालय बन गया।
- 2001 में विनिवेश मंत्रालय का गठन किया गया
- लेकिन 2004 में, मंत्रालय को बंद कर दिया गया और एक स्वतंत्र विभाग के रूप में वित्त मंत्रालय में विलय कर दिया गया।
- बाद में, 2016 में विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) कर दिया गया। अब, DIPAM विनिवेश के लिए एक नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : भारत में विनिवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. पिछले दो दशकों में केवल 1 सार्वजनिक उपक्रम का निजीकरण किया गया है।
2. पिछले 32 सालों में सरकार सिर्फ 8 साल में ही विनिवेश लक्ष्य हासिल कर पाई है।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements with reference to Disinvestment in india-

1. In the last two decades only 1 PSU has been privatised.
2. In the last 32 years, the government has managed to achieve its disinvestment target only in 8 years.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 and nor 2

उत्तर : C

मुख्य परीक्षा के संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्नः भारत में विनिवेश की धीमी प्रगति के क्या कारण हैं? इससे निपटने के लिए कदम सुझाएं।

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में भारत में विनिवेश की धीमी प्रगति के कारणों को स्पष्ट करें।
- दूसरे भाग में इससे निपटने के लिए कदमों की चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।